

2011 का विधेयक सं. 30

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरास्थापित किया जायेगा)

लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर-भीतर कतिपय सेवाएं प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पदाभिहित अधिकारी" से, धारा 3 के अधीन कोई सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "पात्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है ;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है ;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "लोक प्राधिकारी" से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से

उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से सारतः वित्त पोषित, कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित हैं ;

- (च) "सेवा का अधिकार" से, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर धारा 4 के अधीन कोई सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;
- (छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से, ऐसा अधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;
- (ज) "सेवा" से, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही कोई ऐसी सेवा, जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;
- (ञ) "नियत समय-सीमा" से कोई सेवा प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को, या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने के लिए अनुजात, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकतम समय-सीमा अभिप्रेत है।

3. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय-सीमा की अधिसूचना- राज्य सरकार समय-समय पर उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय-सीमाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको और जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।

4. नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार- (1) पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसी सेवा प्रदान करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी ऐसे किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी सेवाओं की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षा की गयी है, उसकी सेवाओं की अपेक्षा करने वाले पदाभिहित अधिकारी की पूरी सहायता करेगा और ऐसा अन्य अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित अधिकारी समझा जायेगा।

5. नियत समय-सीमा में कोई सेवा प्रदान कराना.- (1) नियत समय-सीमा, अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या आवेदन प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे किसी आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर या तो उक्त सेवा प्रदान करेगा या आवेदन को नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

6. अपील.- (1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है या जिसे नियत समय-सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, आवेदन के नामंजूर होने या नियत समय-सीमा की समाप्ति होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(2) प्रथम अपील अधिकारी उस पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा।

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी:

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, साठ दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(4) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, उस पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा।

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी, सेवा प्रदान करने के आदेश के साथ-साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निपटारा प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी, धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निपटारा द्वितीय अपील की रीति से किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) दस्तावेजों के पेश किये जाने और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ख) पदाभिहित अधिकारी और अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) ऐसा कोई भी अन्य विषय, जो विहित किया जाये।

7. **शास्ति.**-(1) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो वह ऐसी एकमुश्त राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलंब किया है तो वह ऐसे विलंब के लिए पदाभिहित अधिकारी पर दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) खण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति पदाभिहित अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी प्रस्तावित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर किसी अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी यह आदेश भी दे सकेगा कि उप-धारा (1) या (2) या, यथास्थिति, दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से ऐसी रकम, जो इस प्रकार अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में दी जाये।

(4) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और

युक्तियुक्त कारण बताये बिना इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

8. पुनरीक्षण- इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यक्तित पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार उस आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे आवेदन को साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

9. सद्वावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्वावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

10. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम

केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

11. कठिनाइयों का निराकरण- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन और नागरिकों को सेवाओं का समयबद्ध प्रदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रस्तावित है कि नागरिकों को नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर, विनिर्दिष्ट लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यदि लोक प्राधिकारी नियत कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं तो उन्हें शास्ति संदर्भ करने के लिए दायी बनाया जाना चाहिए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईंप्रिस्त है।

अतःविधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक के निम्नलिखित खंड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को, प्रत्येक ऐसे खण्ड के सामने प्रगणित विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे, अर्थात् :-

ੴ ਪ੍ਰਾਤਿ

के संबंध में

6(6)(ग) ऐसे अन्य मामले विहित करने, जिनके संबंध में प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी;

8 इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन के निपटारे के लिए प्रक्रिया विहित करने;

10 सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GUARANTEED DELIVERY OF
PUBLIC SERVICES BILL, 2011
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the delivery of certain services to the people of the State by public authority within stipulated time limits and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “designated officer” means an officer notified as such for providing a service under section 3;

(b) “eligible person” means a person who is eligible for obtaining a notified service;

(c) “first appeal officer” means an officer who is notified as such under section 3;

(d) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(e) “public authority” means the State Government and its departments and includes any authority or body or institution established or constituted by or under any law made by the State Legislature and owned, controlled or

substantially financed, directly or indirectly, by the funds provided by the State Government;

- (f) “right to service” means right to obtain a service within the stipulated time limit under section 4;
- (g) “second appellate authority” means an officer who is notified as such under section 3;
- (h) “Service” means any service being provided by a public authority which is notified under section 3;
- (i) “State Government” means the Government of Rajasthan;
- (j) “stipulated time limit” means the maximum time allowed to the designated officer for providing a service or to decide an appeal by the first appeal officer as notified under section 3.

3. Notification of services, designated officers, first appeal officer, second appeal authority and stipulated time limit.- The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officer, second appeal authority and stipulated time limits to which and to whom this Act shall apply.

4. Right to obtain service within the stipulated time limit.- (1) The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

(2) The designated officer may seek the assistance of any other officer or employee as he considers it necessary for the proper discharge of his duties under sub-section (1).

(3) Any officer or employee, whose assistance has been sought under sub-section (2), shall render all assistance to the designated officer seeking his assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer or employee, as the case may be, shall be treated a designated officer.

5. Providing a service in the stipulated time limit.- (1)

The stipulated time limit shall start from the date when the application required for obtaining a notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application. Such an application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall, within the stipulated time limit, either provide the service or reject the application and in case of rejection of the application, shall record the reasons in writing and inform the applicant.

6. Appeal.- (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided a service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of the application or the expiry of the stipulated time limit:

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) A second appeal against the decision of the first appeal officer shall lie to the second appellate authority within sixty days from the date on which the decision was made:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of sixty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) (a) The second appellate authority may order the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) Along with the order to provide service, the second appellate authority may impose a penalty according to the provisions of section 7.

(5) (a) If the designated officer does not comply with sub-section (1) of section 5, the applicant aggrieved by such non-compliance may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of the first appeal.

(b) If the designated officer does not comply with the order of providing a service under sub-section (2) of section 6, the applicant aggrieved by such non-compliance may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of the second appeal.

(6) The first appeal officer and second appellate authority shall, while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

- (a) requiring the production and inspection of documents;
- (b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and
- (c) any other matter which may be prescribed.

7. Penalty.- (1)(a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide a service without sufficient and reasonable cause, he may impose a lump sum penalty which shall not be less than five hundred rupees and not more than five thousand rupees.

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing a service without sufficient and reasonable cause, he may impose a penalty at the rate of two hundred and fifty rupees per day, which shall not exceed five thousand rupees for such delay on the designated officer.

(c) The penalty imposed by the second appellate authority under clause (a) or (b) would be recoverable from the salary of the designated officer:

Provided that before imposing any penalty under this sub-section, the person on whom penalty is proposed to be imposed shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide an appeal within the stipulated time limit without assigning sufficient and reasonable cause, he may impose a penalty on the first appeal officer which shall not be less than five hundred rupees and more than five

thousand rupees:

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may also order that such an amount be given as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, as shall not exceed the penalty so imposed.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without assigning sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

8. Revision.- The designated officer or first appeal officer aggrieved by an order of the second appellate authority in respect of imposing of penalty under this Act, may make an application for revision to the officer nominated by the State Government within a period of sixty days from the date of that order. The nominated officer shall dispose of the application in accordance with the prescribed procedure:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain an application after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the application could not be submitted in time for sufficient reason.

9. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made thereunder.

10. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification

or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

11. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State Government is committed to ensure transparent and responsive administration and time bound delivery of services to the citizens. In furtherance of the above commitment it is proposed that the citizens should be provided with a statutory right to obtain specified public services within a stipulated time and if the public authorities fail to provide such services within the stipulated period, they should be made liable to pay penalty.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the matters enumerated against each of such clauses, namely:-

Clause	with respect to
6(6) (c)	prescribing any other matters with respect to which the first appeal officer and the second appellate authority shall have powers of a civil court;
8	prescribing procedure for disposal of an application for revision under this section;
10	Generally to carry out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

2011 का विधेयक सं. 30

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय-सीमाओं
के भीतर-भीतर कतिपय सेवाएं प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और
आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

सीताराम सोनवाल,
उप सचिव।

(श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 30 of 2011

**THE RAJASTHAN GUARANTEED DELIVERY OF
PUBLIC SERVICES BILL, 2011**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

*A**Bill*

to provide for the delivery of certain services to the people of the State by public authority within stipulated time limits and for matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**SITARAM SONWAL,
Deputy Secretary.**

(ASHOK GEHLOT, Minister-Incharge)